

४.२) केंद्र शासनाच्या योजना :-

| अ.क्र. | विभाग             | योजना                     | तपशील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | ग्रामपंचायत विभाग | १५ वा केंद्रीय वित्त आयोग | <p>राज्यातील ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान वितरीत करणे. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांचे कडील शासन निर्णय क्रमांक पंविआ २०२०/प्र.क्र.५९/वित्त-४ दिनांक २६ जून, २०२० अन्वये दिनांक १ एप्रिल, २०२० ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत केंद्रशासनाकडून राज्यातील ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणा साठी राज्याला मुलभूत/बेसिक अनुदान (अनटाईड) व बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरूपात निधी प्राप्त होणार आहे. प्रस्तुत अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आणि ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरासाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहे</p> <p>सदर निधीची परिगणना सन २०११ च्या जनगणनेनुसारची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या निकषांनुसार केली आहे. प्रस्तुत निधी १) मुलभूत/बेसिक अनुदान (अनटाईड) व २) बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरूपात प्राप्त होणार असून ते ५०% - ५०% च्या प्रमाणात विभागण्यात आले आहे.</p> |
| 2      | ग्रामपंचायत विभाग | केंद्रीय स्वामित्व योजना  | <p>पंचायती राज मंत्रालयाची 'स्वामित्व योजना' जमिनीचे पार्सल मॅप करण्यासाठी, मालमत्ता मालकांना कायदेशीर मालकी कार्ड (मालमत्ता कार्ड/टायटल डीड) जारी करण्यासाठी आणि ग्रामीण घरमालकांना 'हक्कांचे रेकॉर्ड' प्रदान करण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करते. पंचायती राज मंत्रालयाची केंद्रीय क्षेत्रातील योजना 'स्वामित्वा' ही योजना माननीय पंतप्रधान महोदय यांनी राष्ट्रीय पंचायती राज दिनी (२०२०-२०२१) १ राज्यांमध्ये योजनेचा पायलट टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर २४ एप्रिल २०२१ रोजी देशभरात सुरु केली. ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीचे मॅपिंग करून आणि मालमत्ता मालकांना कायदेशीर मालकी कार्ड (मालमत्ता कार्ड/मालमत्ता करार) देऊन ग्रामीण वस्ती असलेल्या ("आबादी") भागात मालमत्तेची स्पष्ट मालकी स्थापित करण्याच्या दिशेने ही योजना एक सुधारणात्मक पाऊल आहे. ही योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य महसूल विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग आणि भारतीय</p>          |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | सर्वेक्षण विभाग यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी राबविण्यात येत आहे. या योजनेत मालमत्तेचे मुद्रीकरण सुलभ करणे आणि बँक कर्ज सक्षम करणे, मालमत्तेशी संबंधित वाद कमी करणे, व्यापक ग्रामीण पातळीवरील नियोजन, खऱ्या अर्थाने ग्राम स्वराज साध्य करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने एक पाऊल असेल |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|